राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 292

प्रगति

समाचार पत्र
सितम्बर 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

एनआईआरडीपीआर में सीपीएमई ... परियोजना पद्धति की योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में

3 एनआईआरडीपीआर में पीएमई ... परियोजना पद्धति की योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में

विषय-सूची

5
तेलंगाना गवर्नर ने एनआईआरडीपीआर के लिए अपने पहले दौरे में क्षमता निर्माण का दिलाया विश्वास

6
एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप सम्मेलन 2019 आयोजित

8
आरसेटी - कौशल प्रशिक्षण संस्थायें जहां दिव्यांग भी सक्षम हैं

10
डॉ. रजनी वाक्कलंका द्वारा गौरैया के संरक्षण पर लाइब्रेरी व्याख्यान

11
प्रथम आईजीबीसी रेटेड नेट ज़ीरो एनर्जी - प्लेटिनम आरसेटी भवन का जोधपुर में किया गया उद्घाटन

12
अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ एमजीएनआरईजीएस के अभिसरण पर टीओटी

13
भारत में स्वच्छता के बारे में बेहतर नतीजे हासिल करने में समुदाय – उन्मुख दृष्टिकोण मदद कर सकती है – एनआईआरडीपीआर में सरकारी दौरे पर डॉ. कमल कर

14
उन्नत भारत अभियान, तेलंगाना के सहभागी संस्थाओं के नोडल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम

15
ग्रामीण विकास नेतृत्व पद्धति पर ४ था प्रबंधन विकास कार्यक्रम

18
ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन हेतु सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र, एनआईआरडीपीआर द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी

एनआईआरडीपीआर में सीपीएमई ... परियोजना पद्धति की योजना और कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद का योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र (सीपीएमई), लोक नीति एवं सु-शासन स्कूल (बॉक्स 1) के तहत तीन केंद्रों में से एक है, जिसे परियोजना-आधारित कार्यान्वयन और अपेक्षित परिणामों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए अनिवार्य बनाया गया है। डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के कारण हाल के दिनों में सीपीएमई की भूमिका को महत्व मिला है ।

सरकारी निधियों के उपयुक्त उपयोग, बजटीय सुधारों को लागू करने के लिए बहुवर्षीय ढांचे के भीतर उत्पादन और परिणाम आधारित बजट के लिए वार्षिक प्रक्रियाओं के पुनरीक्षण की सुविधा के लिए राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्था (एनआईटीआई) के गठन पर, भारत सरकार द्वारा व्यय और वितरण / परिणामों के बीच संबंध स्थापित करने और व्यय के एक विकसित मध्यम अवधि के ढांचे की स्थापना के लिए पहल की गई है। राज्य सरकारों को 2017-18 के बजट से इसी तरह की बदलाव करना है ।

उपरोक्त के मद्देनजर, सार्वजनिक व्यय प्रबंधन के दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव आया है जिसमें इनपुट, आउटपुट और परिणामों के साथ बजटीय संयोजन जुड़ा हुआ है। इस प्रकार, यह बजट तैयारी के पद्धति में मूलभूत परिवर्तन का सुझाव देता है जो मुख्य रूप से बजटीय परिव्यय के साथ आउटपुट / परिणामों को जोड़ने पर केंद्रित है: (i) एनआईटीआई के परामर्श में संबंधित मंत्रालयों / विभागों द्वारा योजनाओं में आवंटन का विभाजन (ii) आऊटपुट / वितरणों को मापनीय / मात्रात्मक शर्तों में दिए जाने की आवश्यकता है । (iii) एनआईटीआई बजटीय परिव्यय जिसके लिए पर्याप्त अग्रिम योजना आवश्यकता होती है के संबंध में प्रत्येक योजना के लिए मात्रात्मक वितरण / आऊटपुट / परिणामों पर निर्णय सहित एनआईटीआई के परिणाम बजटों की जिम्मेदारी लेगी । इस प्रकार प्रत्येक मंत्रालय / विभाग वितरण को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत आवश्यकताओं का अस्थायी मूल्यांकन करेगा । इसमें दिशानिर्देश, परियोजना निर्माण के लिए प्रक्रिया / तंत्र, संस्थागत संरचना, मूल्यांकन, अनुमोदन और अन्य विविध मुद्दों के लिए समय सीमा शामिल हैं।

> **ग्रामीण विकास के लिए नियोजित गतिविधियों के अलावा, सीपीएमई वर्तमान नीतियों के लिए उपयुक्त विभिन्न अनुकूलित गतिविधियाँ भी करता है**

इस प्रकार, वित्तीय संसाधनों के अधिक प्रभावी अनुप्रयोग को सुनिश्चित करने और योजना / कार्यक्रम आबंटन को अधिक केंद्रित और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए इसका उद्देश्य परियोजना मोड पर प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के उन्नत योजना और कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व करना है। परियोजना योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन में उपयुक्त कार्यप्रणालियों को विकसित और लागू करने के जनादेश को प्राप्त करने के लिए, सीपीएमई ने विभिन्न विषयों और उप-विषयों पर काम किया है जो मजबूत परियोजना रिपोर्ट बनाने में महत्वपूर्ण हैं (बॉक्स 2) ।

बॉक्स 2: लोक नीति एवं सु-शासन स्कूल – रणनीति

निम्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए वंचित परिणाम प्राप्त करने में ग्रामीण विकास कार्यक्रम / परियोजना चक्र के सभी चरणों / स्तरों के माध्यम से प्रभावी सार्वजनिक नीति और सुशासन में

- उपयुक्त कार्यप्रणालियों का विकास और अनुप्रयोग **(योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र),**
- बहु-हितधारक अनुबंध की वृद्धित भूमिका को विकसित करना और सुविधाजनक बनाना **(कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, पीपीपी एवं जन कार्रवाई केंद्र)** और
- उन्नत सेवा सुपुर्दगी के लिए उपकरण / सु-शासन के माडलों का सृजन करना और लोकप्रिय बनाना **(सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र)**

वर्तमान नीतियों द्वारा सृजित महत्व ध्यान में रखते हुए, केंद्र को (i) योजना, निगरानी और मूल्यांकन में उपयुक्त उपकरण और तकनीकों को विकसित और प्रसारित का अधिदेश दिया गया है । (ii) ग्रामीण विकास में परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान देने के साथ अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विचार, डिजाइनिंग, आयोजन; (iii) ग्रामीण गरीबों के लिए उन्नत गुणात्मक जीवन को प्राप्त करने के लिए पीएमई उपकरण और तकनीकों के उपयोग पर ग्रामीण विकास अधिकारियों और अन्य लोगों को सुसज्जित करने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना; और (iv) भारत के विभिन्न भागों से मामला अध्ययन के रूप में सफल नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रियाओं का प्रलेखन और हितधारकों के लिए परिचयात्मक दौरों का आयोजन। सीपीएमई मुख्य रूप से व्यवस्थित नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उपयुक्त टूल्स और तकनीकों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित

बॉक्स 2:

विषय	उप विषय
साक्ष्य आधारित नीति	नीति के प्रामाणिक साक्ष्य और सूत्रीकरण
	मूल्यांकन
व्यवस्थित योजना	स्थिति और हितधारक विश्लेषण
	समस्या का विश्लेषण और वस्तुपरकता
	रणनीति डिजाइनिंग
	निश्चित विकास संकेतकों के साथ परियोजना डिजाइनिंग
	जोखिम प्रबंधन रणनीतियाँ
	व्यवहार्यता परीक्षण के लिए मूल्यांकन
आउटपुट-परिणाम आधारित	अच्छी तरह से परिभाषित परिणाम
बजटिंग	परियोजना मोड कार्यान्वयन के उपयोग के लिए प्रस्तावित
	धन के विरूद्ध परिणामों की वैधता
अपेक्षित बदलाव के लिए	विकास संकेतकों पर डेटा बेस प्रबंधन
परिणामों की लगातार ट्रैकिंग	एम एंड ई पेशेवरों की समर्पित टीम की स्थिति
(निगरानी)	परिणाम आधारित प्रबंधन (परिणाम श्रृंखला, मैट्रिक्स, आदि)
	मध्य कोर्स के लिए मध्यस्थ परामर्श विकसित करना
उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित	स्कोप के आधार पर स्व-मूल्यांकन / मध्यावधि मूल्यांकन
करना - आउटपुट, परिणाम और	सूचना के प्रमुख पहलुओं का महत्वपूर्ण परीक्षा (तीसरा)
प्रभाव (मूल्यांकन)	नीति सुधार और वकालत की तैयारी

करता है, जिसमें परिणामों का प्रतिपादन (आउटपुट-परिणाम-प्रभाव) और उपयुक्त विकास संकेतक शामिल हैं। परियोजना योजना और परिणाम आधारित प्रबंधन के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालिसिस (एलएफए) आधारित प्रतिपादन का अनुप्रयोग। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों / योजनाओं / परियोजनाओं के परियोजना मोड कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन करने, अध्ययन करने के लिए निगरानी, मूल्यांकन और प्रभाव मूल्यांकन योजनाओं के लिए थियरी ऑफ चेंज - (टीओसी) आधारित डिजाइनिंग।

इस दिशा में, सीपीएमई विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है:
(i) सभी स्तरों पर और परियोजना मोड कार्यान्वयन के सभी चरणों में ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाना;

(ii) ग्रामीण लोगों के रहने की स्थिति में सुधार के लिए कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास हस्तक्षेपों के प्रदर्शन को जानना और

(iii) साक्ष्य-आधारित नीतियों, रणनीतियों और परियोजनाओं को विकसित करने में मदद के लिए एम एंड ई अध्ययनों पर इनपुट / फीडबैक-आधार प्रदान करना।

सीपीएमई ग्रामीण विकास के कई चुनौतियों से निपटने से संबंधित काम की आवश्यकता को पूरा करने की गतिविधियों को पूरा करता है। व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए, सीपीएमई विभिन्न गतिविधियाँ करता है अर्थात
(i) विभिन्न हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण;
(ii) निगरानी और कार्यक्रमों एवं योजनाओं की मूल्यांकन के लिए अध्ययन।

राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी), राज्य ग्रामीण विकास विभागों का योजना विंग, राज्य और जिला स्तर पर कार्यरत एम एण्ड ई प्रभाग, आदि लक्षित प्रमुख हितधारक हैं। यद्यपि जनादेश बहुत बड़ा और व्यापक है, केंद्र की रणनीतियों को प्राथमिकता-आधारित दृष्टिकोण से पूरा किया जाता है, मुख्य रूप से विभिन्न विकास के वास्तविक समय डैशबोर्ड प्रबंधन की बढ़ती मांग को देखते हुए परिणाम, संकेतक, जवाबदेही, प्रदर्शन माप के डिजाइनिंग पर कौशल प्रदान करने के लिए

मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, जे-पाल, आदि जैसे संस्थानों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम, आंतरिक संकाय के लिए एम एंड ई टूल और तकनीकों को अद्यतन करने के लिए प्रयासरत हैं, यह इस संबंध में नवीनतम विकासों के साथ निरंतर गतिविधि है। इसके अलावा, सीपीएमई सरकार की नीतियों के बदलते परिदृश्य और प्राथमिकताओं के साथ वर्तमान जरूरतों और प्रवृत्ति पर अधिक ध्यान देने के साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए उपयुक्त टूल विकसित / मजबूत करने के लिए कार्य करता है। सीपीएमई सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और दाताओं को अपनी निगरानी और मूल्यांकन नीतियों, रणनीतियों और प्रणालियों को मजबूत करने के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाएं प्रदान करता है और संकेतक और माप योजनाओं के चयन सहित उनके एम एंड ई फ्रेमवर्क की प्रदर्शन के लिए उनके परिवर्तन सिद्धांत कार्यक्रम को डिजाइन करने में मदद करता है ताकि साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले डेटा का उपयोग करके उनके संगठनों में आवश्यक परिवर्तन ला सके।

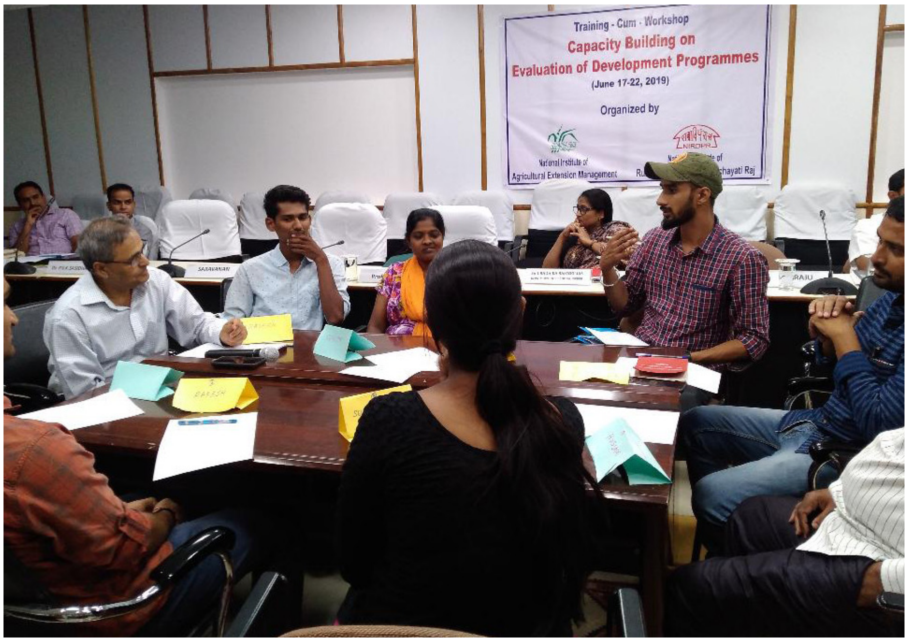

सीपीएमई द्वारा आयोजित विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के दौरान एक पारस्परिक सत्र

प्रो. जी. वेंकट राजू
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
योजना, निगरानी और मूल्यांकन केंद्र
कवर पेज डिजाइन: **श्री वी.जी. भट्ट**

तेलंगाना के गवर्नर ने एनआईआरडीपीआर में अपने पहले दौरे के दौरान क्षमता निर्माण की गारंटी दी

एनआईआरडीपीआर के दौरे के दौरान दीप प्रज्वलित करते हुए डॉ. तमिलिसाई सौंदराजन, राज्यपाल, तेलंगाना साथ है (बाएं से) डॉ. पी. शिवराम, डॉ. डब्ल्यू.आर. रेड्डी, श्री सुरेंद्र मोहन और श्रीमती राधिका रस्तोगी

सभा को संबोधित करते
डॉ. तमिलिसाई सौंदराजन

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क के दौरे के दौरान
डॉ. तमिलिसाई सौंदराजन

तेलंगाना के नवनियुक्त राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सौंदराजन ने राज्य में पदभार ग्रहण करने के बाद गुरुवार 19 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेंद्रनगर को पहला दौरा किया । इस अवसर पर, उन्होंने पंचायतों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 'सतत ग्रामीण विकास पहल भी प्रारंभ किया।

संस्थान के परिसर में स्थित विकास सभागार में आयोजित उद्घाटन सत्र में अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यू.आर रेड्डी, एनआईआरडीपीआर ने कहा कि संस्थान अपने

60 वर्षों के इतिहास साथ प्रशिक्षण, अनुसंधान और शैक्षणिक समर्थन के माध्यम से ग्रामीण भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

उन्होंने कहा कि, ''ग्रामीण स्तर पर कार्यभार संभालने वाले सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को दैनंदिन मामलों में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में, संस्थान में हर साल देश भर से लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाता है। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले प्रतिभागियों की संख्या को बढ़ाने की मांग की जा रही है और हम इस दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं ।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने जोर दिया कि संस्थान ने जम्मू-कश्मीर में जमीनी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने की पहल की है । "संस्थान ने मिशन मोड पर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जिससे उपलब्ध संसाधनों से विकास योजना बनाने में मदद मिली है । इस परियोजना को 2 अक्टूबर, 2018 को शुरू किया गया था। संस्थान 2 अक्टूबर, 2019 से इस परियोजना को शुरू करेगा'' उन्होंने कहा ।

दर्शकों को संबोधित करते हुए तेलंगाना के राज्यपाल, डॉ. तमिलिसाई सौंदराजन ने कहा कि एनआईआरडीपीआर के हरे भरे परिसर का दौरा करके वे खुश हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान 'जैसे कार्य और अन्य ने इस बात कि पुष्टि की है कि सरकार ग्रामीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि "वर्तमान समय में, गाँव वालों के पास भौतिक ज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी की कमी है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है और 60 प्रतिशत भारतीय आबादी ग्रामीण है और क्षमता निर्माण के लिए हमेशा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। "

राज्यपाल ने कहा कि संस्थान को हर साल प्रशिक्षित लोगों की संख्या को बढ़ानी चाहिए। उन्होंने परिसर में प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की सराहना की। उन्होंने एक किसान जिसको अपनी जमीन की कीमत का एहसास तब हुआ जब किसी अन्य व्यक्ति ने उसे उजागर किया के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनायी तत्पश्चात अपने भाषण का समापन किया ।

डॉ. फ्रैंकलिन लल्तिखुंमा, आईएएस, रजिस्ट्रार और निदेशक (प्रशा.), ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। श्री सुरेंद्र मोहन, आईएएस, राज्यपाल के सचिव, संस्थान के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों सहित कई प्रतिभागियाँ और छात्रों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

उसके बाद उसी दिन, राज्यपाल ने विभिन्न स्थायी ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने के लिए संस्थान के ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा किया और महिलाओं / प्रौद्योगिकी साझेदारों के साथ बातचीत की।

दौरे के समय, ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में तमिलनाडु और तेलंगाना के स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित ग्रामीण उत्पादों की प्रदर्शनी-सह-बिक्री की व्यवस्था की गई थी ।

- सीडीसी पहल

एनआईआरडीपीआर में ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप सम्मेलन - 2019 संपन्न

आरआईएससी-2019 के दौरान सभा को संबोधित करते हुए श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री; मंच पर उपस्थित अन्य लोग (बाएं से) श्री मोहम्मद खान, श्री अरविंद धर्मपुरी, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, डॉ. रंजीत रेड्डी, डॉ. के.एस. एम. राघव राव और डॉ. रमेश सक्तिवेल

27 और 28 सितंबर, 2019 को दो दिनों के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान के अभिनव एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा ग्रामीण नवप्रवर्तक स्टार्ट-अप सम्मेलन - 2019 का आयोजन किया गया । यह नवप्रवर्तकों और स्टार्ट-अप के विस्तृत क्षेत्र के लिए निर्मित एक मंच है जिसमें वे अपने नवाचारों, उत्पादों को प्रदर्शित कर सकते और उसी के बारे में बात कर फंडिंग एवं नेटवर्क समर्थन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते है । इस आयोजन ने स्कूल और कॉलेज के छात्रों को आरआईएससी -2019 के भाग के रूप में ग्रामीण नवोन्मेष डिजाइन चैलेंज घटक के तहत ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए नवीन विचारों और डिजाइनों के साथ आने का अवसर प्रदान किया था।

कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने की, जबकि डॉ. रंजीत रेड्डी और श्री अरविंद धर्मपुरी, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा और डॉ. के.एस.एम.एस. राघव राव, निदेशक, खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूरु सम्मानित अतिथि थे ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति आरआईएससी -2019 के दौरान प्रदर्शित एक नवाचार को संचालित करते

मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम शुरु हुआ।

डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह सम्मेलन श्रृंखला में 3 रे स्थान पर है और सम्मेलन का उद्देश्य नवप्रवर्तकों, नवोदित स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना और उनसे तथा छात्रों से विचारों एवं अवधारणाओं को प्राप्त करना है ताकि संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञों की मदद से परिष्कृत करके उन्हें बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि युवक मुद्दों को अवसरों में परिवर्तित करना चाहिए और उद्यमी मॉडल को विकसित करना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में स्टार्ट-अप इन्क्यूबेशन सेंटर और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जबकि एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए प्लेटफॉर्म विकसित किया है। पिछले दो वर्षों में, अर्थात् 2017 और 2018 में आयोजित कार्यक्रम को याद करते हुए, महानिदेशक ने कहा कि पैकेजिंग के क्षेत्रों में देखी गई कमियों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से काफी हद तक संबोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम के दौरान मिलने वाली विशेषज्ञ सलाह से काफी हद तक लाभान्वित होंगे।

डॉ. रमेश सक्तिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआईएटी ने अपने संबोधन में कहा कि 9 0 नवप्रवर्तक और 4 8 स्टार्ट-अप अपने प्रोटोटाइप और उत्पादों के साथ भाग ले रहे है। इसके अलावा कॉलेजों के 58 छात्र, स्कूलों के 68 छात्र अपने अभिनव विचारों के साथ भाग ले रहे है।

माननीय संसद सदस्य श्री अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि उन्हें इस कार्यक्रम का भाग होने पर गर्व है और उन्होंने कहा कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए उसी को बढ़ावा देने की अवधारणा की पहचान करने में एनआईआरडीपीआर का प्रयास वास्तव में सराहनीय है।

माननीय संसद सदस्य डॉ. रंजीत रेड्डी ने कहा कि नवोन्मेषण जीवन रेखा हैं और इस बात को उद्धृत किया कि मुर्गी उत्पादों के उत्पादन में भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर है जो कि एक व्यक्ति के नवोन्मेषण के कारण हुआ है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन लाभदायी विचारों को सामने लाने में सक्षम होगा और उन नवोन्मेषकों की पहचान करेगा जो स्थानीय जीवन को बदलने में सक्षम हो सकते हैं।

सीएफटीआरआई के निदेशक डॉ. के.एस.एम.एस. राघव राव ने कहा कि नवाचार एक नवजात शिशु की तरह है और एक विचार को एक अवधारणा में बदलने में आवश्यक कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सीएफटीआरआई किसानों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि टिकाऊ नवीकरण मॉडल विकसित किया जा सके। उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण पर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण आदि के लिए सहयोग में काम करने के लिए एनआईआरडीपीआर के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के लिए की खुशी व्यक्त की।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री जी ने सतत आवास प्रौद्योगिकियों - डीजी, बंगलो पर एक वृत्तचित्र (वीडियो) जारी करने के साथ-साथ सीआईएटी-आरटीपी द्वारा निकाली गई दो पुस्तकों आरआईएससी-2018 की रिपोर्ट और आरआईएससी-2019 की कार्यवाही का विमोचन किया।

इसके अलावा, एनआईआरडीपीआर और सीएफटीआरआई, मैसूरु, मारीगोल्ड थ्रेड्स, हैदराबाद और बायोटेक रिनीवेबल एनर्जी, केरल जैसे संस्थानों के बीच तीन समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया।

मुख्य भाषण प्रस्तुत करते हुए, माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि एनआईआरडीपीआर में आयोजित इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मैं बेहद खुश हैं, जो ग्रामीण भारत के परिवर्तन के लिए भारत सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों को लागू करने में बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गांव कार्रवाई का मुख्य क्षेत्र है।

"हालांकि विकास के लिए प्रयास किए गए हैं, फिर भी बहुत कुछ किया जाना है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।" उन्होंने कहा कि युवा इस मानसिकता में हैं कि एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही जीवन में बसने का केवल एक क्षेत्र है। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए इस मानसिकता के कारण, नवाचारों ने पीछे की सीट ले ली है। उन्होंने आरआईएससी जैसे मंच के आयोजन करने के लिए एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की, जो निश्चित रूप से नवोन्मेषकों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में पैसा लगा रही है।

धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए, श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शक, ने कार्यक्रम में भाग लेने और इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भारत के सभी भागों से आए प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देने के अलावा मुख्य भाषण में उन लाइनों पर काम करने के लिए एनआईआरडीपीआर को मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया।

प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रीन ऊर्जा, स्थायी आजीविका, टिकाऊ आवास, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुजुर्गों का देखभाल एवं अपशिष्ट से संपत्ति जैसे क्षेत्रों में 220 स्टाल लगे थे जिसमें नवाचारों और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा विकसित हाइड्रोलिक मड ब्लॉक मशीन के कामकाज का निरीक्षण करने के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न स्टालों पर प्रतिभागियों से बातचीत की।

बाद में, माननीय मुख्य अतिथि ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में बायोटेक रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकी भागीदार जिनके साथ एमओयू का आदान-प्रदान हुआ था के द्वारा स्थापित बायोगैस रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया।

दोपहर में, प्रतिभागियों के लाभ के लिए पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था और निम्नलिखित दो विषयों पर छात्रों को संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जोड़ा गया:

१. समावेशी विकास के लिए ग्रामीण नवाचार - स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ - डिजाइनिंग और आईपीआर का महत्व

२. ग्रामीण इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय और विपणन सहायता - स्कोप, अवसर और योजनाएँ

कार्यक्रम के दूसरे दिन, अर्थात, 28 सितंबर, 2019 को साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए अपने संबोधन में, उन्होंने दिन के दौरान निरीक्षण किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्पादों को याद करते हुए ऐसे उपयोगी नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेटर्स की सराहना की। नवाचारों और नवप्रवर्तकों को बढ़ावा देने हेतु एक ही मंच पर उन सभी को लाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए एनआईआरडीपीआर की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय को ग्रामीण परिवर्तन की ओर जिन्हें अपनाने में मदद मिलेगी।

माननीय मुख्य अतिथि, साध्वी निरंजन ज्योति ने आरटीपी में एनआईआरडीपीआर द्वारा स्थापित की जा रही एकीकृत डेयरी विकास इकाई की आधारशिला रखी जो ग्रामीण समुदाय, बेरोजगार युवाओं आदि के लिए प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन केंद्र के रूप में काम करेगी।

दिन के दौरान, डॉ. विक्रम सिंह तोमरफो द्वारा प्रतिभागियों के लाभ के लिए प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत की गई।

मुख्य अतिथि, साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदर्शकों में से 12 को विशेष मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के अलावा 14 नवप्रवर्तकों, 11 स्टार्ट-अप और 41 (21 स्कूल के छात्रों, 20 कॉलेज के छात्रों) को योग्यता प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए।

आरआईएससी -2019 के दौरान प्रदर्शित नवाचार को देखते हुए गणमान्य व्यक्ति

आर-सेटी कौशल प्रशिक्षण संस्थान जहां पर दिव्यांग भी सक्षम होते हैं

आर-सेटी में प्राप्त प्रशिक्षण से फ्लैशलाईट टॉर्च की मरम्मत करते हुए श्री सुजाराम

सफल उद्यमी का नाम:
श्री सुजाराम

आर-सेटी का नाम:
आईसीआईसीआई का भोपालगढ़ सैटिलाइट सेंटर
आर-सेटी जोधपुर

कौशल प्रशिक्षण का नाम:
घरेलू विद्युत उपकरण सेवा उद्यमी (घरेलू गृह उपकरण रिपेयरिंग और सर्विसिंग पाठ्यक्रम)

क्रेडिट लिंकेज:
विश्व योजना के तहत मंजूर रुपये 1,00,000 (एक लाख)

"हालांकि विकास के लिए प्रयास किए गए हैं, फिर भी बहुत कुछ किया जाना है, जिसके लिए सरकार प्रयास कर रही है।" उन्होंने कहा कि युवा इस मानसिकता में हैं कि एक सरकारी नौकरी प्राप्त करना ही जीवन में बसने का केवल एक क्षेत्र है। अंग्रेजों द्वारा लगाए गए इस मानसिकता के कारण, नवाचारों ने पीछे की सीट ले ली है। उन्होंने आरआईएससी जैसे मंच के आयोजन करने के लिए एनआईआरडीपीआर के प्रयासों की सराहना की, जो निश्चित रूप से नवोन्मेषकों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार नवाचारों को आगे बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में पैसा लगा रही है।

धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए, श्री मोहम्मद खान, वरिष्ठ परामर्शक, ने कार्यक्रम में भाग लेने और इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु भारत के सभी भागों से आए प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अन्य गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद देने के अलावा मुख्य भाषण में उन लाइनों पर काम करने के लिए एनआईआरडीपीआर को मार्गदर्शन देने के लिए माननीय मुख्य अतिथि का धन्यवाद किया।

प्रदर्शनी का उद्घाटन श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया, जिसमें कृषि और संबद्ध गतिविधियों, ग्रीन ऊर्जा, स्थायी आजीविका, टिकाऊ आवास, पेयजल और स्वच्छता, स्वास्थ्य और बुजुर्गों का देखभाल एवं अपशिष्ट से संपत्ति जैसे क्षेत्रों में 220 स्टाल लगे थे जिसमें नवाचारों और उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। उन्होंने ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क द्वारा विकसित हाइड्रोलिक मड ब्लॉक मशीन के कामकाज का निरीक्षण करने के अलावा अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ विभिन्न स्टालों पर प्रतिभागियों से बातचीत की।

बाद में, माननीय मुख्य अतिथि ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क में बायोटेक रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकी भागीदार जिनके साथ एमओयू का आदान-प्रदान हुआ था के द्वारा स्थापित बायोगैस रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया।

दोपहर में, प्रतिभागियों के लाभ के लिए पैनल चर्चा का आयोजन किया गया था और निम्नलिखित दो विषयों पर छात्रों को संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जोड़ा गया:

1. समावेशी विकास के लिए ग्रामीण नवाचार - स्टार्ट-अप इको-सिस्टम को बढ़ाने के लिए रणनीतियाँ - डिजाइनिंग और आईपीआर का महत्व
2. ग्रामीण इनोवेटर्स और स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय और विपणन सहायता - स्कोप, अवसर और योजनाएँ

कार्यक्रम के दूसरे दिन, अर्थात, 28 सितंबर, 2019 को साध्वी निरंजन ज्योति, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया। प्रतिभागियों के लिए अपने संबोधन में, उन्होंने दिन के दौरान निरीक्षण किए गए विभिन्न नवाचारों और उत्पादों को याद करते हुए ऐसे उपयोगी नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए इनोवेटर्स की सराहना की। नवाचारों और नवप्रवर्तकों को बढ़ावा देने हेतु एक ही मंच पर उन सभी को लाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए एनआईआरडीपीआर की सराहना की, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण समुदाय को ग्रामीण परिवर्तन की ओर जिन्हें अपनाने में मदद मिलेगी।

माननीय मुख्य अतिथि, साध्वी निरंजन ज्योति ने आरटीपी में एनआईआरडीपीआर द्वारा स्थापित की जा रही एकीकृत डेयरी विकास इकाई की आधारशिला रखी जो ग्रामीण समुदाय, बेरोजगार युवाओं आदि के लिए प्रशिक्षण-सह-प्रदर्शन केंद्र के रूप में काम करेगी।

दिन के दौरान, डॉ. विक्रम सिंह तोमरफो द्वारा प्रतिभागियों के लाभ के लिए प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत की गई।

मुख्य अतिथि, साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रदर्शकों में से 12 को विशेष मान्यता प्रमाणपत्र प्रदान करने के अलावा 14 नवप्रवर्तकों, 11 स्टार्ट-अप और 41 (21 स्कूल के छात्रों, 20 कॉलेज के छात्रों) को योग्यता प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए।

डॉ. रजनी वक्कलंका द्वारा गौरैया के संरक्षण पर पुस्तकॉलय व्याख्यान

पुस्तकॉलय व्याख्यान के दौरान दर्शकों के साथ बातचीत करते हुए डॉ. रजनी वक्कलंका

20 सितंबर, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, राजेन्द्रनगर के प्रलेखन एवं संचार विकास केन्द्र (सीडीसी) द्वारा पुस्तकॉलय व्याख्यान का आयोजन किया गया । इस वार्ता का विषय 'गौरैया का संरक्षण' था और डॉ. रजनी वक्कलंका महिनी – पीपल फॉर मदर अर्थ के डॉ. रजनी वक्कलंका द्वारा व्याख्यान दिया गया ।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी ने विशेष अतिथि का स्वागत किया। डॉ. रजनी वक्कलंका ने जैव विविधता को परिभाषित करने के साथ बात शुरू की (पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीव रूपों की विविधता और प्रकार)। जैव विविधता को आगे चलकर प्रजातियों की विविधता, आनुवांशिक विविधता और पारिस्थितिकी विविधता में वर्गीकृत किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के 12 मेगा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। एक मेगा-विविध देश वह है, जहां पूरे ग्रह में मौजूद 60- 70 प्रतिशत वनस्पतियों और जीवों को एक ही देश में पाया जाता है।

डॉ. रजनी ने बताया कि जैव विविधता के गंभीर खतरे हैं: i) वन्यजीवों के निवास स्थान का विखंडन और विनाश ii) आक्रामक प्रजातियों का विस्तार iii) विभिन्न प्रकार के प्रदूषण iv) जलवायु परिवर्तन (तापमान में परिवर्तन विभिन्न प्रजातियों के प्रजनन को प्रभावित कर रहा है) v) प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग।

वक्ता ने जैव विविधता के महत्व पर जोर दिया अर्थात एक प्रजाति की उत्तरजीविता दूसरे प्रजातियों पर निर्भर करती है। उन्होंने पशुओं के शव को खाने वाले लुप्तप्राय हो रहे गिद्ध का उदाहरण दिया, जिसने डायक्लोफेनाक (दर्द को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा) का सेवन किया था। पक्षी उन कीटों को खाते हैं, जो फसलों को संक्रमित करते हैं। पक्षी उपज के प्राकृतिक संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।

बुलफ्रॉग भारत में पाई जाने वाली मेंढक प्रजातियों में से एक है। 1970 के दशक में, मेंढकों की टांगो को अन्य देशों में निर्यात किया गया क्योंकि यह एक प्रसिद्ध व्यंजन था। कुछ ही वर्षों में उनकी संख्या काफी हद तक कम हो गई। डब्ल्युडब्ल्युएफ (वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर) की रिपोर्ट के अनुसार, 1970 के बाद से 60 फीसदी वन्यजीव समाप्त हो गए है।

भारत पक्षियों की 1,224 प्रजातियों के लिए घर है, जहाँ तेलंगाना राज्य में 400 प्रजातियाँ हैं, और उनमें से 220 प्रजातियाँ हैदराबाद में पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि गौरैया के गायब होने के पीछे मुख्य कारण हैं:

I) घर के पैटर्न में बदलाव और शहरीकरण
ii) वायु जल और मिट्टी का प्रदूषण
iii) कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग

चीन में, जब माओजेडांग तुंग शासन कर रहे थे, तो उन्होंने चावल के अनाज को बचाने के लिए देश के सभी गौरैया की सामूहिक हत्या करने का आदेश दिया। उन्होंने लोगों को वही चावल खिलाने की योजना बनाई थी। हालांकि, अगली फसल बहुत कम रही। पक्षी वास्तव में फसलों पर हमला करने वाले कीटों को खाते हैं, और सभी गौरैयों को मार दिए जाने कारण उत्पादन प्रभावित हुआ।

हमें पक्षियों की आवश्यकता क्यों है?

- वे सक्रिय रूप से वन और वृक्ष विकास में भाग लेते हैं
- उन्हें प्राकृतिक माली कहा जाता है क्योंकि वे बीज वाहक में मदद करते हैं
- वे परागण निषेचन में मदद करते हैं

बाद में, डॉ. रजनी ने उनके कॉलोनी में गौरैया के संरक्षण से जुड़े अनुभव को साझा किया। उन्होंने नेहरू जूलॉजिकल पार्क, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य स्थानों में जागरूकता सत्र चलाया हैं। वक्ता ने लकड़ी के बचे हुए टुकडों का उपयोग करके गौरैयों के लिए घोंसले का निर्माण करने के बारे में विस्तार से बताया। गौरैया मानव आबादी के आसपास रहती हैं और वे अपने घोंसले बनाने के लिए पेड़ों का चयन नहीं करती हैं। वे अपने पंखों को साफ रखने के लिए नियमित रूप से खुद को साफ करते हैं, जो बदले में उन्हें अपने शिकारियों से तेजी से उड़ने में मदद करता है।

उन्होंने कहा कि जब से प्रयास शुरू हुआ है, पक्षियों की पहली जोड़ी को हमारे द्वारा स्थापित आधुनिक घोंसले में आकर रहने के लिए छह साल लग गए। व्याख्यान के बाद, उन्होंने दर्शकों द्वारा उनसे पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दिए।

डॉ. आकांक्षा शुक्ला ने एनआईआरडीपीआर की ओर से वक्ता को धन्यवाद दिया। संस्थान के शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों सहित छात्रों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

-सीडीसी पहल

जोधपुर में प्रथम आईजीबीसी निर्धारित नेट जीरो एनर्जी - प्लेटिनम आर-सेटी भवन का उद्घाटन किया गया।

श्रीमती अलका उपाध्याय, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 11 सितंबर, 2019 को जोधपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आर-सेटी) भवन का उद्घाटन किया। श्री गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक, श्रीमती पी. चम्पकवल्ली, परियोजना निदेशक, आरएसईटीआई परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस भवन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा "नेट ज़ीरो एनर्जी - प्लैटिनम" रेटिंग से सम्मानित किया गया है। यह देश का पहला भवन है जिसे प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है।

आईसीआईसीआई आर-सेटी हब और स्पोक मॉडल के माध्यम से राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर जिलों में कौशल विकास गतिविधियों का संचालन करता है। जयपुर और जोधपुर में 19 गैर-आवासीय केंद्रों के साथ दो आवासीय केंद्र हैं। केंद्र आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 30 से अधिक ट्रेडों में 10 से 45 दिनों के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता हैं। 18-45 वर्ष की आयु के कौशल प्रशिक्षण प्रशिक्षुओं को उपनगरों और शहरों की ओर पलायन किए बिना अपने गांवों में स्थायी आजीविका अर्जित करने के लिए अपना स्वयं का रोजगार शुरू करने में मदद करता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद, प्रशिक्षुओं को मुफ्त-में टूलकिट प्रदान किए जाते हैं ताकि वे अपने उद्यम तुरंत शुरू कर सकें। स्थापना के बाद से, आईसीआईसीआई, आर-सेटी ने 88,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया है जिनमें से 55 प्रतिशत महिलाएं थीं।

एक उपयुक्त शिक्षण माहौल प्रशिक्षुओं को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए, आईसीआईसीआई ने इस ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण किया है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल हैं। पारंपरिक भवन की तुलना में इस भवन में केवल ५० प्रतिशत बिजली और पानी की खपत होने की संभावना है।

राजस्थान सरकार ने भूमि प्रदान किया और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद ने इस सुविधा के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता जारी किया । भवन की आधारशिला राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा रखी गई।

"नेट ज़ीरो एनर्जी - प्लैटिनम" रेटेड इमारत की उदाहरणात्मक विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- जोधपुर से 'चित्तर पत्थर' नामक स्थानीय रेतीले पत्थर का उपयोग किया गया है जो मौसम की चरम स्थितियों से कम प्रभावित होता है।
- प्रभावी शीतलन के लिए भवन में मोटी दीवारें, पत्थर के ग्रिल और खुले गलियारे हैं।
- पर्यावरण अनुकूल स्थापनाएँ जैसे कि छतों पर सोलर सिस्टम और पूरी तरह से प्राकृतिक फाइटोर मीडिएशन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ और पौधे होते हैं जिनकी जड़ें गंदे पानी को साफ करती हैं। पुनर्नवीनीकृत पानी का उपयोग परिसर में लैंडस्केप के फ्लिशंग और सिंचाई के लिए किया जाता है।
- बाहरी परिसर में रोशनी के लिए एलईडी आधारित लाइटिंग व्यवस्था और स्टैंडअलोन सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना की गई।
- भवन के अंदर तापमान बनाए रखने के लिए कुल छत टाइलों का उपयोग किया गया।
- ऊर्जा के पर्याप्त उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्टार रेटेड उपकरणों, ऊर्जा कुशल डीसी पंखों और एक ऊर्जा निगरानी प्रणाली की व्यवस्था की गई।
- प्राकृतिक डे-लाइट का उपयोग करना जो भवन के ८० प्रतिशत से अधिक कार्यात्मक क्षेत्रों में इसके विशेष डिजाइन के कारण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है।
- ड्रिप सिंचाई सुविधा के साथ जल संरक्षण और सूखा-सहिष्णु किस्म के भूनिर्माण के लिए वर्षा जल संचयन।
- दिव्यांगों के लिए रैंप और टॉयलेट के साथ पूरी तरह से सुलभ बिल्डिंग डिजाइन

उपर्युक्त लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल सुविधाओं की सूची को अन्य आर-सेटी के प्रायोजक बैंकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो विभिन्न जिलों में भवनों का निर्माण शुरू करना बाकी है।

श्रीमती अल्का उपाध्याय, अपर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने भवन का उद्घाटन किया

अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ एमजीएनआरईजीएस के अभिसरण पर टीओटी

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ डॉ. एस. ज्योतिस, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडब्ल्युई (दाएं से पहली पंक्ति चौथे), डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई (बाएं से पहली पंक्ति चौथे), डॉ. दिगंबर चिमनकर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई (दाएं से पहली पंक्ति तीसरे) और डॉ. पी. अनुराधा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई (दाईं ओर से दूसरी पंक्ति में दूसरे)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद के मजदूरी रोजगार केन्द्र (सीडब्ल्युई) द्वारा बेहतर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के लिए अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अभिसरण पर तीन दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी), आयोजित किया गया। 11 -13 सितंबर, 2019 के दौरान इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया।

प्रतिभागी आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों से आये थे। इनमें एसआईआरडी, एसआरएलएम और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी शामिल थे।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) भारत में एक रोजगार सृजन पहल है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से स्थायी प्राकृतिक और मानव निर्मित संपत्ति के सृजन द्वारा ग्रामीण आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना देना है। एमजीएनआरईजीएस के कार्यान्वयन ने ग्रामीण विकास में सहयोग देने के लिए अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ अभिसरण को बढ़ावा दिया है। ऐसे सहयोग के कई उदाहरण हैं जिसने ग्रामीण आजीविका को बढ़ाया है; सतत प्राकृतिक संपत्तियों के सृजन में समर्थन दिया है, पारिस्थितिकी की व्यवहार्यता, जलवायु परिवर्तन के लिए समुदाय की दत्तक क्षमता को सुधारना आदि।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य एमजीएनआरईजीएस के तहत प्राकृतिक-परिसंपत्तियों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए प्रकृति-आधारित समाधान पारिस्थितिकी सेवाओं पर बुनियादी समझ प्रदान करना रहा है, ताकि सतत मानव आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीएस के तहत सामाजिक-आर्थिक लाभों के मूल्यांकन और प्राकृतिक संपत्तियों की निगरानी के तरीकों, एमजीएनआरईजीएस नियोजन प्रक्रिया में प्रकृति आधारित समाधानों को शामिल करने की क्षमता बढ़ाने और एसडीजी और जलवायु प्रूफिंग के स्थानीयकरण के लिए जीपीडीपी के साथ एकीकरण को प्रारंभ किया जा सके।

कार्यक्रम का उद्घाटन सीडब्ल्युई के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, डॉ. ज्योतिस सत्यपालन ने किया। उन्होंने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम और सत्रों की आवश्यकता को बताया। बाद में, उन्होंने जलवायु कार्यवाही पर एमजीएनआरईजीएस की भूमिका पर एक सत्र लिया।

सुश्री श्रिपर्णा अय्यर और उनके सहयोगी श्री नवनीत नाइक और श्री नबाघन ओझा की अध्यक्षता में आईपीई ग्लोबल, नई दिल्ली की टीम, इस कार्यक्रम के स्त्रोत व्यक्ति थे। उन्होंने जलवायु प्रूफिंग एमजीएनआरईजीए (जलवायु परिवर्तनशील विकास कार्यक्रम के लिए आधारभूत संरचना का अवलोकन) पर सत्र चलाए। उन्होंने ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में काम करते हुए अपने अनुभव को साझा किए।

सामाजिक लेखा परीक्षा केन्द्र के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. धीरजा ने एमजीएनआरईजीएस के तहत पारदर्शिता, जवाबदेही और सामाजिक लेखा परीक्षा पर बात की। अभिनव एवं उपयुक्त तकनोलॉजी केन्द्र के एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष डॉ. रमेश सक्थिवेल, एसोसिएट प्रोफेसर और उनकी टीम द्वारा सतत आजीविका के लिए नो-कास्ट, लो-कास्ट तकनोलॉजी पर सत्र कवर किया गया। डॉ. नागराज राव ने सतत आजीविका के लिए एमजीएनआरईजीएस-एनआरएलएम अभिसरण पर सत्र चलाया।

डॉ. दिगंबर चिमनकर, डॉ. नीरज मिश्रा, डॉ. पी. अनुराधा और मजदूरी रोजगार के कर्मचारियों ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

भारत में स्वच्छता के संबंध में बेहतर नजीजों को प्राप्त करने में समुदाय - नेतृत्व दृष्टिकोण मदद कर सकता है – एनआईआरडीपीआर में सरकारी दौरे पर डॉ. कमल कर

डॉ. कमल कर

भारत जैसे विकासशील देशों में, स्वच्छता और इसके प्रभाव पर ज्ञान अनिवार्य है और इस उद्यम के क्रम में, 11 सितंबर, 2019 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान में समुदाय उन्मुख संपूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) फाउंडेशन, कोलकाता के डॉ. कमल कर द्वारा व्याख्यान दिया। इनके पास २०१० में सीएलटीएस प्रारंभ करने से पहले विश्व बैंक, डब्ल्युएसपी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डीएफआईडी, यूनिसेफ, यूएनडीपी, अयरलैंड एड, जीटीजेड और केयर, प्लान इंटरनेशनल, वाटर एड, गेट्स फाउंडेशन इत्यादि सहित कई अंतरराष्ट्रीय एनजीओ जैसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने का समृद्ध अनुभव है। 2010 में डॉ. कर पशुधन उत्पादन, कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के प्रसिद्ध विशेषज्ञ तथा सामाजिक और भागीदारी विकास में विशेष रुचि रखते है।

डॉ. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीआरआई द्वारा स्वागत भाषण के उपरांत, डॉ. कर ने 'भारत और अन्य देशों की राष्ट्रीय स्वच्छता नीतियों' के बारे में विस्तार से बात की, जिसमें उन्होंने देश भर में लोगों द्वारा स्वच्छता के बारे में प्रदान जानकारी किस तरह से स्वीकार किया जा रहा है विशेषकर ग्रामीण भारत के बारे में विस्तार से बताया।

स्वच्छता पर अंतर्राष्ट्रीय जानकारी रखने वाले डॉ. कर ने कहा कि "लोगों के व्यवहार में बदलाव समय की आवश्यकता है। वैश्विक स्तर पर कुल आबादी के 2.4 बिलियन लोगों के पास शौचालय नहीं है और उनमें से 946 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) का लक्ष्य दुनिया भर में कम से कम 77 प्रतिशत लोगों को स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। दुनिया की 68 फीसदी आबादी ने शौचालयों में सुधार किया है, जो इस बात पर जोर देता है कि 700 मिलियन से अधिक लोगों के पास इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शौचालय होनी चाहिए, "उन्होंने कहा।

उचित स्वच्छता तक पहुँच के स्तर में १९९९ से "पश्चिमी एशिया में ५० प्रतिशत, उत्तरी अफ्रीका में ४१ प्रतिशत और सब सहारा अफ्रीका में १७ प्रतिशत है। स्वच्छता की सुविधा के बिना वाले जनसंख्या में मुख्य रूप से एशिया, उप-सहारा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन आता है। । संख्या में, दक्षिणी एशिया - ९५३ मिलियन, उप सहारा अफ्रीका - ६९५ मिलियन, पूर्वी एशिया - ३३७ मिलियन, दक्षिण पूर्वी एशिया - १७६ मिलियन, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन - १०६ मिलियन के पास स्वच्छता सुविधाओं तक कोई पहुंच नहीं है। भारत उन देशों में नंबर एक पर है, जहां खुले में शौच होता है, इसके बाद इंडोनेशिया आता है"।

स्वच्छता के लिए बेहतर पहुंच सुविधा प्रदान करने की इस प्रक्रिया के तहत, डॉ.कर ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय समुदाय की पद्धतियों और गतिशीलता पर विचार करने के बाद कानून बनाना चाहिए। इस दृष्टिकोण की सहायता से, समुदाय के प्रमुखों द्वारा मुख्य निर्णय लिए जाएंगे, जो उनके निवास स्थान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्णय लेंगे। डॉ. कर ने ग्रामीण बांग्लादेश में खुले में शौच के मुद्दे को कवर करने वाली एक बीबीसी वीडियो स्टोरी और ग्रामीणों को सीएलटीएस का उपयोग करके शौचालय निर्माण के लिए कैसे प्रेरित किया गया का भी उल्लेख किया । उन्होंने सीएलटीएस के कुछ घटकों को विस्तृत रूप से बताया जो इस प्रकार हैं:

- सरकारी अधिकारियों का रवैय्या और व्यवहार
  1. व्यक्तिगत
  2. पेशेवर
  3. संस्थागत
- पर्यावरण के अनुकूल
  १. अंतर-संस्थागत समन्वय
  २. राष्ट्रीय प्रोटोकॉल/बजट
- सीएलटीएस दृष्टिकोण के तहत उपयोग किए गए उपकरण और तकनीक
  १. प्री-ट्रिगर
  २. ट्रिगरिंग
  ३. पोस्ट-ट्रिगरिंग
  ४. पोस्ट-ओडीएफ कार्रवाई

नीति ढांचे को निर्दिष्ट करते हुए, उन्होंने सिफारिश की कि आवश्यक अभिसरण प्राप्त करने के लिए अंतर-संस्थागत समन्वय होना चाहिए। डॉ. कर ने कहा कि तिमोर-लेस्ते दुनिया का पहला देश है जिसे खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया गया था। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों ने अफ्रीकी देशों के साथ-साथ ओडीएफ को कम करने में काफी प्रयास किए हैं। इथियोपिया में, खुले में शौच को नियंत्रित करने के लिए 2007 में सीएलटीएस और कमेंट्री रैपिड अप्रेज़ल प्रोटोकॉल (सीआरएपी) प्रारंभ किए गए। उन्होंने कहा कि इन सभी प्रयासों से संबंधित देशों में स्वच्छता के संबंध में काफी बदलाव आया है।

सतत विकास लक्ष्य 6.2 के अनुसार, इसका लक्ष्य खुले में शौच को समाप्त करके सभी के लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता एवं सफाई तक पहुंच प्राप्त करना है और 2030 तक महिलाओं एवं लड़कियों की जरूरतों और कमजोर स्थितियों पर विशेष ध्यान देना है। स्वच्छ भारत मिशन की संभावनाओं की ओर इशारा करते हुए वक्ता ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य ठोस और तरल प्रबंधन (एसएलडब्ल्युएम) परियोजनाओं को शुरू करके स्वच्छता में सुधार के लिए लोगों में बेहतर स्वच्छता व्यवहार को बढ़ावा देना है।

ओडीएफ के मूल स्थान का हवाला देते हुए, जिसे निर्माण के बाद शौच के लिए उपयोग कर सकते है के बारे में कहते हुए, डॉ. कर ने कहा कि स्थानीय संस्कृति और पद्धतियों पर विचार करके ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया जा सकता है। व्याख्यान के भाग के रूप में, उन्होंने ग्रामीण भारत में लोग कैसे पशुओं को आश्रय प्रदान करने और अन्य चीजों को संग्रहीत करने के लिए शौचालय का उपयोग कर रहे हैं के बारे में बताया जिससे अन्य दिलचस्प चर्चा को मौका मिला।

उनके व्याख्यान के बाद, डॉ. कार ने दर्शकों के साथ बातचीत की और उपस्थित अन्य सदस्यों के साथ अपने कुछ मूल्यवान क्षेत्र के अनुभव साझा किए। डॉ. शिवराम, पी एंड एच, सीएफएल द्वारा समापण भाषण प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन के प्रति दर्शकों को ज्ञान देने के लिए वक्ता को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर और श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक ने की । व्याख्यान के दौरान डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएफएल, डॉ. आकांक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी, डॉ. देबप्रिया, एसोसिएट प्रोफेसर, सीपीजीएस, डॉ. नीरज मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर, सीडब्ल्युई, डॉ. एस.के सत्यप्रभा, सहायक प्रोफेसर सीजीजी एवं पीए, डॉ. अनुराधा, सहायक प्रोफेसर, सीडब्ल्युई और पीजीडीआरडीएम छात्र उपस्थित थे।

-सीडीसी पहल

उन्नत भारत अभियान, तेलंगाना के सहभागी संस्थानों के नोडल अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और सहभागी प्रशिक्षण कार्यक्रम

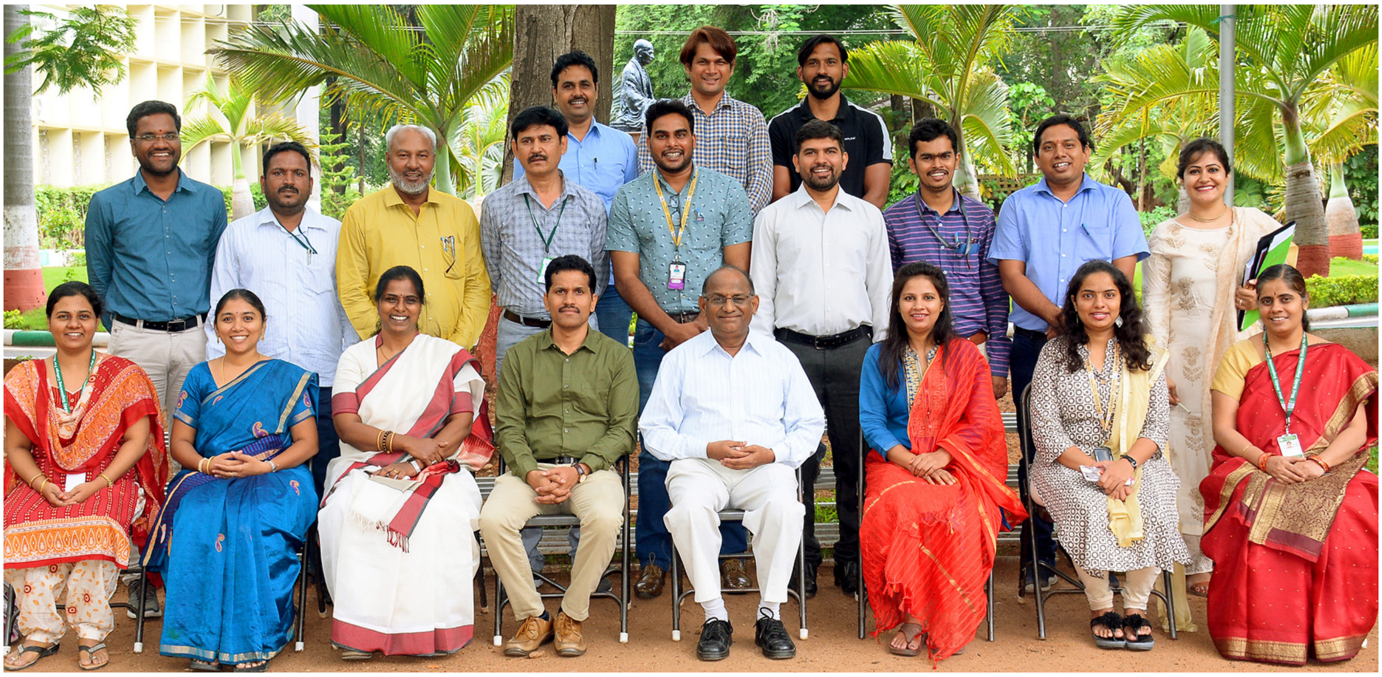

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य प्रतिभागियों के साथ डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएचआरडी (दाएं से पहली पंक्ति में चौथे) और डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (बाएं से पहली पंक्ति में चौथे)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के मानव संसाधन विकास केन्द्र ने 26-28 अगस्त, 2019 के दौरान तीन दिवसीय राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण और भागीदारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस पाठ्यक्रम में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से तेलंगाना क्षेत्र के लिए उन्नत भारत अभियान के तहत भाग लेने वाले संस्थानों के नोडल अधिकारियों को लक्षित किया गया । इस पाठ्यक्रम को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया।

कार्यक्रम के उद्देश्य थे

(1) प्रतिभागियों को ग्राम विकास योजना तैयार करने के लिए रूपरेखा से परिचित कराना

(2) उन्हें भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पीआरए) के उपकरणों और तकनीकों और ग्राम विकास योजना तैयार करने में इसका उपयोग के बारे में उन्मुख करना

(3) प्रतिभागियों को ग्राम विकास योजना तैयार करने में स्थिति विश्लेषण के महत्व के बारे में जागरूक करना

(4) सतत विकास तरीकों को तैयार करने के लिए नियंत्रित और मुक्त धन का उपयोग करने की रणनीतियों के बारे में उन्हें समझाना और

(5) कार्य योजना तैयार करने के लिए मिशन अंत्योदय ढांचे का उपयोग।

तेलंगाना राज्य के नौ सहभागी संस्थानों के कुल 18 संकाय सदस्यों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एनआईआरडीपीआर संकाय के अलावा, आईआईटी - नई दिल्ली के प्रोफेसर प्रियांका कौशल के साथ वीडियो कॉन्फरेंस आयोजित किया गया । प्रतिभागियों के साथ बातचीत के दौरान, उन्होंने उन्हें उन्नत भारत अभियान चरण 2.0 के उद्देश्य और स्वरूप के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम के विषयों में यूबीए चरण 2.0 पर अवलोकन पीआरए उपकरण और तकनीकों की मूल बातें, ग्राम विकास योजना के लिए रूपरेखा, यूबीए के तहत प्रौद्योगिकी, पीआरए पर व्यावहारिक अनुभव और क्षेत्र दौरे के माध्यम से ग्राम विकास योजना शामिल हैं।

कार्यक्रम की अवधि के दौरान, प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत ले जाया गया, जहां उन्हें सामाजिक मानचित्रण और अन्य पीआरए तकनीकों जैसे कि ट्रांसेक्ट वॉक, रैंकिंग मैट्रिक्स, आदि पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त हुआ, क्षेत्र पर प्रतिभागियों ने कई स्थानीय समाचार देने वालों के साथ गाँव के केंद्र से क्षेत्र के बाहरी सीमा तक ट्रांसेक्ट वॉक करते हुए पीआरए गतिविधि शुरू किए। गाँव के ट्रांसेक्ट वॉक को पूरा करने के बाद, समुदाय के सदस्यों द्वारा सामाजिक नक्शा तैयार किया गया जिससे उन्हें परिवारों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर के बारे में जानने में मदद कर सकता था।

पाठ्यक्रम टीम ने डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर को समापण सत्र में आमंत्रित किया । अपने भाषण में, उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए यूबीए उद्देश्यों के महत्व को दोहराया और तकनीकी संस्थानों, उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि के साथ, ग्रामीण पारिस्थितिकी में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं के बारे में बताया वह चाहते थे कि वर्तमान पीढ़ी (छात्र) ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझने के लिए गांव के निवासियों के साथ बातचीत करने और ग्रामीण विकास के लिए योगदान करने के लिए इस अवसर का उपयोग करें।

कार्यक्रम का संयोजन डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास केंद्र और डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र ने किया।

ग्रामीण विकास नेतृत्व पर 4 वाँ प्रबंधन विकास कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति में चौथे), श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस , उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (दाएं से पहली पंक्ति में तीसरे), पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएचआरडी (बाएं से पहली पंक्ति में तीसरे), डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, सीआरआई (दूसरी पंक्ति में) (बाएं से दूसरे) डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, सीएचआरडी (बाएं से दूसरी पंक्ति में तीसरे)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद ने सतत ग्रामीण विकास के लिए आदर्श पारिस्थितिकी बनाने के अपने जनादेश के साथ, जिला कलेक्टरों / जिलाधिकारियों, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, आदि पर विशेष जोर देने के साथ जिला स्तर के अधिकारियों को तैयार करने के विचार को अत्यंत महत्व देता है । तदनुसार, एनआईआरडीपीआर ने ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया हैं। इस तरह के तीन कार्यक्रम अब तक अच्छी प्रतिक्रिया और परिणामों के साथ आयोजित किए गए हैं।

इसे जारी रखते हुए, मानव संसाधन विकास केन्द्र ने एनआईआरडीपीआर में 22-26 जुलाई, 2019 के दौरान ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम पर एक राष्ट्र-स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जो संभावित जिला कलेक्टरों / जिला मजिस्ट्रेटों के लिए श्रृंखला में चौथा है।

इस कार्यक्रम में छह राज्यों के अपर परियोजना निदेशक, सहायक आयुक्त, पंचायत के निदेशक, आयुक्त, उप मंडलीय अधिकारी, निदेशक, उप-सीईओ, सहायक जिला आयुक्त और वरिष्ठ जिला मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने वाले कुल 12 प्रतिभागी भाग लिए।

इस कार्यक्रम का आयोजन जिला मजिस्ट्रेट / जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका के महत्व को देते हुए उनके मजिस्ट्रियल कार्यों के अलावा गरीबी, स्वच्छता, बेरोजगारी, महिला सशक्तीकरण आदि को संबोधित करने के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों / कार्यों / अभिनव हस्तक्षेपों की पहल करने के लिए किया गया । यह भी माना जाता है कि जिला कलेक्टर / मजिस्ट्रेट के रूप में जिले में पोस्टिंग के 2-3 वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उनकी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए अधिकारियों और उनके प्रभावी कामकाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि और ग्रामीण भारत को बदलने में ग्रामीण विकास की भूमिका ध्यान में रखते हुए और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए, एनआईआरडीपीआर ने भावी जिला कलेक्टरों जिलाधिकारी के लिए 'ग्रामीण विकास नेतृत्व पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम' पर राष्ट्र स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है।

कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिकारियों की मौलिक दक्षताओं जैसे कि ज्ञान, दृष्टिकोण, मूल्य, कौशल और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं को तेज करना है जो कि ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक हैं। इसका उद्देश्य जिलों में प्रचलित विभिन्न सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के लिए कैरियर के प्रारंभिक चरण में प्रतिभागियों को उनके संभावनाओं की पहचान कराना और जिला-विशिष्ट समस्यांओं के लिए त्वरित समाधान प्राप्त करने के लिए एनआईआरडीपीआर और अन्य समान एजेंसियों जैसे विभिन्न सहायक संस्थानों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक करना है।

श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने औपचारिक रूप से प्रतिभागियों का स्वागत किया और इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी उन्मूलन की कई योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित गरीबी पर जोर दिया । उन्होंने कहा कि यद्यपि हम गरीबी को कम करने में सक्षम हैं, लेकिन हमें इसके पूर्ण उन्मूलन के लिए बहुत लंबा समय लगता है । हमें कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से लागू करने की जरूरत है।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, उन्होंने जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट के रूप में ग्रामीण विकास के लिए काम करने के एक बार के अवसर के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पांच-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न ग्रामीण विकास के मुद्दों (मातृ मृत्यु दर, बाल मृत्यु, कुपोषण, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पर युवा अधिकारियों के दिमाग को वे जिला कलेक्टरों / जिला मजिस्ट्रेटों के रूप में कार्यभार ग्रहण करने से पहले तेज करना है ताकि वे ग्रामीण पारिस्थितिकी में कुशलता से योगदान दे सकें। इसके अलावा, उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि डीसी / डीएम के रूप में 2-3 साल की अवधि में उनके जिलों के लिए दूर दृष्टि रखें और उन विज़न को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी योजना तैयार करें। उन्होंने उल्लेख किया कि यह अवसर उनके लिए सीमित है क्योंकि उनके पास केवल २-३ साल का समय है। ऐसी परिस्थितियों में, उन्हें ऐसी मुद्दों को उठाना चाहिए जो ग्रामीण क्षेत्रों को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अधिकारी 1,000 दिनों के पोषन अभियान के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को प्राप्त करने या पंचायती राज से संबंधित मुद्दों, ठोस और अपशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन और कार्बन फुटप्रिंट मुद्दों से निपटने के लिए समान विचार रखने वाले लोगों / संस्थानों से जुड़ सकते हैं ग्रामीण विकास के लिए बेहतर तकनीक का अनुप्रयोग, पंचायत स्तर (स्थानीय नेतृत्व के लिए महत्व) पर योजना में सहभागी दृष्टिकोण, आदि रख सकते है । समापन भाषण में, उन्होंने प्रशिक्षण के महत्व पर जोर दिया और कहा कि अधिकारियों को क्षेत्र के बारे में अपडेट रखने के लिए ग्रामीण विकास विषयों पर नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के भाग के रूप में पौधे लगाते हुए प्रतिभागीगण

पांच दिवसीय कार्यक्रम के सत्र और उद्देश्य को पूर्व में आयोजित तीन राउंड के कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों द्वारा दिए गए फीडबैक और साथ ही, श्री एस.एम विजयनानद, पूर्व मुख्य सचिव, केरल और महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किए गए । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पांच दिनों के दौरान निम्नलिखित विषयों को कवर किया गया: जिला नियोजन में जिला कलेक्टरों की भूमिका को समझना, भारत में ग्रामीण विकास और हाल के कार्य, जलवायु परिवर्तन और परमाणु संसाधन प्रबंधन, नैतिकता और ग्रामीण विकास, भारत में शिक्षा की चुनौतियां - मनोविज्ञान के सिद्धांत, सम्रग्र वित्त, बुनियादी शिक्षा और ग्रामीण विकास, ग्रामीण गरीबों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक जुटाव, कौशल और ग्रामीण सशक्तीकरण, विकेंद्रीकृत शासन और पंचायतों की भूमिका, अधिकार आधारित विकास - सामाजिक जवाबदेही और पारदर्शिता, भारत में जनजातीय आबादी के विशेष संदर्भ में स्वास्थ्य की स्थिति, नवाचार और प्रशासन में सुधार, ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए संसाधन के रूप में बच्चों के अलावा, प्रतिभागियों ने जिला विजन योजना तैयार किए और परिसर में स्थित ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा भी किया।

प्रत्येक सत्र के लिए वी. भास्कर, आईएएस (सेवानिवृत्त); डॉ. एस.वी. रंगाचार्युलु, पूर्व प्रोफेसर, एनआईआरडीपीआर; प्रोफेसर, ज्योतिस सत्यपालन, एनआईआरडीपीआर; श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, डी डी जी, एनआईआरडीपीआर; सुश्री चित्रा अनंत, आर्ट ऑफ़ लिविंग, हैदराबाद; डॉ. कमला वी. मुकुंका, सेंटर फॉर लर्निंग, बेंगलुरु; प्रो. श्रीराम, आईआईएम बेंगलुरु; श्रीमती शांता सिन्हा (रेमन मैग्सेसे अवार्डी); श्री जयेश रंजन, आईएएस, प्रमुख सचिव, आईटी, तेलंगाना; श्री हरि किशोर, आईएएस, कार्यकारी निदेशक, कुडुम्बश्री, केरल; श्री एस.एम. विजयानंद, आईएएस (सेवानिवृत्त), पूर्व मुख्य सचिव, केरल; सुश्री सोम्या किदंबी, निदेशक,

प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर

एसएसएएटी, तेलंगाना, प्रो. सी. धीरजा, एनआईआरडीपीआर; डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम, संस्थापक और अध्यक्ष, जीआरएएम, मैसूर; श्री पी. बाला किरण, आईएएस, निदेशक, पर्यटन विभाग, केरल; श्री देवांशु चक्रवर्ती, स्वतंत्र सलाहकार, यूनिसेफ; और डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस, एनआईआरडीपीआर जैसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ नौकरशाह, शिक्षाविद, व्यावसायकर्ता और विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों को व्याख्यान-सह-चर्चा, वाद-विवाद, प्रदर्शनी दौरा, समूह अभ्यास, ग्राम अध्यक्षों द्वारा व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करना (सफल कहानियां), और प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुति जैसे प्रशिक्षण तरीकों के मिश्रण द्वारा वितरित किया गया।

क्षेत्र प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में नवीन विकास प्रथाओं के बारे में जानने के लिए हाज़िपल्ले गाँव के लिए प्रदर्शनी दौरे का आयोजन किया गया। इसके अलावा, प्रतिभागियों को कान्हा शांति वनम, हैदराबाद में अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणालियों से परिचित कराया गया। ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क, एनआईआरडीपीआर में प्रदर्शित विभिन्न क्षेत्रों के लागत प्रभावी, स्थानीय संसाधन-आधारित और पर्यावरण अनुकूल ग्रामीण प्रौद्योगिकियों के प्रसार के बारे में प्रतिभागियों ने एक लाइव प्रदर्शन का अनुभव प्राप्त किया।

कार्यक्रम के अंत में, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया / मूल्यांकन देने के लिए कहा गया । उनकी प्रतिक्रिया से देखा गया कि प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को अत्यधिक मूल्यवान पाया है। प्रतिभागियों द्वारा बताए गए इस कार्यक्रम के कुछ लर्निंग निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

"इसने अच्छे और प्रभावी प्रशासन के बारे में मेरा दृष्टिकोण बदल दिया है"

''लोगों की बेहतरी और क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कलेक्टर के सीमित कार्यकाल को लागू करने के संभाविततरीकोंऔरसाधनोंकेबारेमेंसीखा"

"जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें से अधिकांश हमारे दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों से जुड़े थे, इसलिएयहनिश्चितरूपसेमेरीमददकरेगा"

"अधिकांश व्याख्यान में सभी विषय शामिल हैं और विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक हमारी मदद करेंगे"

"अभ्यास के दौरान प्राप्त किए गए नवीन विचारों का मैं उपयोग करूंगा"

"इसने हमारी नेतृत्व शक्ति को बढ़ाया है"

"विकास इंजन के रूप में आजीविका के अवसरों को नया और विस्तारित करने की कोशिश करना"

प्रतिभागियों ने व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम बहुत सही समय पर आया है और यह उनकी दक्षताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य जोड है, यह उन्हें कार्य गतिविधियों को बेहतर रूप से प्रदर्शन करने में मदद करेगा।

प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बहुत उपयोगी पाया। मूल्यांकन रिपोर्ट में, प्रतिभागियों ने देखा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के बाद प्रशिक्षु के सभी तीन आयाम, अर्थात्, ज्ञान 94 प्रतिशत), कौशल 88 प्रतिशत) और दृष्टिकोण 90 प्रतिशत) में सुधार हुआ है। कार्यक्रम की कुल प्रभावशीलता 87 प्रतिशत है।

डॉ. लखन सिंह, सहायक प्रोफेसर, डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, मानव संसाधन विकास केंद्र और डॉ. आर. रमेश, एसोसिएट प्रोफेसर, ग्रामीण आधारभूत संरचना केन्द्र ने कार्यक्रम का आयोजन किया।

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्‌घाटन के दौरान बाएं से – डॉ. डब्ल्यु.आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, डॉ. ज्ञानमुद्र, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए, डॉ. कृष्ण रेड्डी, एसोसिएट प्रोफेसर, सीएनआरएम और डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर (पाठ्यक्रम निदेशक), सुशासन और नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजीपीए)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर), हैदराबाद में 3-30 सितंबर 2019 के दौरान सुशासन और नीति विश्लेषण (सीजीजीपीए) केंद्र द्वारा 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन' पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

एशिया, दक्षिण एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका जैसे 18 विकासशील देशों के कुल 26 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण में भाग लिया। इनमें ग्रामीण विकास, विकेंद्रीकरण और कृषि व्यवसायी शामिल हैं। आईटीईसी देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया।

निम्नलिखित उद्देश्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया । शासन की नैतिकता और मूल्यों की सराहना करना; शासन, सिद्धांत और व्यवहार के संदर्भ को समझाना और अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय (भारत) के सुशासन दृष्टिकोण को सिखाना । 'सुशासन: एक अंतरराष्ट्रीय अनुशासनात्मक परिवर्तनकारी अवधारणाएं'; 'सुशासन: समकालीन समाज में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन'; 'सुशासन: जमीनी स्तर पर पहल और सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए अग्रणी'; "राज्य प्रदर्शन के अनुभवजन्य कारक के रूप में नेतृत्व शासन 'और' फ्लैगशिप कार्यक्रम-प्रभावी कार्यान्वयन में शासन की भूमिका' जैसे मॉड्यूल को कवर करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में जोर दिया गया ।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु.आर. रेड्डी, आईएएस ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और सुशासन पर उनके अनुभवों को उजागर किया। प्रतिभागियों के साथ पारस्परिक सत्र के दौरान, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हम सभी सरकारी अधिकारियों के रूप में अपना काम कर रहे हैं, तो हमें "गुड गवर्नेंस" से पहले उपसर्ग "गुड" की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हममें से हर एक की भूमिका होती है कि हम कितने उत्साह से कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर गरीब लोगों के इन मुद्दों को संबोधित करते हैं।

संपूर्ण पाठ्यक्रम में विभिन्न प्रख्यात वक्ताओं (आंतरिक और आमंत्रित) द्वारा प्रतिभागियों के लिए सत्र आयोजित किए गए जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया जैसे कि जिनमें 'सुशासन-अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, विचलन प्रक्रिया, और सुशासन -भारतीय दृष्टिकोण (डॉ.ज्ञानमुद्रा, एनआईआरडीपीआर) , 'विश्वव्यापी शासन संकेतकों द्वारा मापी गई शासन की कार्यप्रणाली आयाम (डॉ. पी. ललिता, निदेशक, 3 एच कैटलिस्ट), 'सेवा वितरण में जेंडर संबंधी चिंता' (डॉ. माधुरी, एनआईआरडीपीआर), 'लोकतांत्रिक शासन की पहल के माध्यम से कुशल, प्रभावी सेवा वितरण' '(डॉ. अजय कुमार सिंह, आईपीएस (सेवानिवृत्त),' ग्रामीण विकास प्रबंधन में सुशासन के लिए सेवा वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता' (श्री जेम्स वर्गीज, आईएएस, प्रमुख सचिव (सेवानिवृत्त) और') ग्रामीण विकास के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियाँ' (डॉ. रमेश सक्तिवेल, एनआईआरडीपीआर) आदि व्याख्यान रहे।

सुशासन पद्धतियों पर प्रतिभागियों के ज्ञान को मजबूत करने के लिए विभिन्न सामाजिक जवाबदेही टूलों पर व्याख्यान आयोजित किए गए जैसे कि सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी), नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी (डॉ. के. प्रभाकर, पाठ्यक्रम निदेशक, एनआईआरडीपीआर), 'सामाजिक लेखापरीक्षा (डॉ. धीरजा, एनआईआरडीपीआर), ग्रामीण विकास के लिए प्रभावी स्थानीय शासन प्रबंधन रणनीतियों के लिए पीआरए टूल (डॉ. अरुणा जयमणि, एनआईआरडीपीआर) और 'जवाबदेही एवं पारदर्शिता के लिए टूल' - आरटीआई 'सकल मामला अध्ययन पर चर्चा' (श्री राजेंद्र सिंह कपूर, कोर फैकल्टी, एचआईपीए, शिमला)।

साथ ही ई-गवर्नेंस के माध्यम से "खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के लिए प्रभावी कार्यान्वयन: आंध्र प्रदेश राज्य में एईपीडीएस का मामला" (डॉ. के. प्रभाकर, एनआईआरडीपीआर), 'प्रभावी ग्रामीण विकास के लिए वित्तीय समावेशन और उद्यमशीलता' (डॉ. एम. श्रीकांत), एनआईआरडीपीआर) और समूह चर्चा और अभ्यास "समुदाय संचालित स्व-शासित मॉडल ग्राम - गंगादेवीपल्ली का एक मामला" (डॉ. के. प्रभाकर, एनआईआरडीपीआर) जैसे विषयों को भी कवर किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में शासन में आईसीटी और आईटी की भूमिका को भी कवर किया गया जिसमें मुख्य रूप से भारत में ई-गवर्नेंस: अवधारणा, पहल और सफलता की कहानियां "(डॉ. राजशेखर, डीडीजी, एनआईसी, हैदराबाद); 'आईटी कृषि – ग्रामीण विकास" (डॉ. एस. सेंथिल विनयागम, एनएएआरएम); "ग्रामीण विकास में भू-संसूचना प्रौद्योगिकी" (डॉ. एन.एस. आर प्रसाद, एनआईआरडीपीआर); 'एसएचजी के लिए केस स्टडी लोकवाणी और आईटी - केस स्टडी चर्चा" (श्री के. राजेश्वर, एनआईआरडीपीआर); "कृषि शासन प्रणाली में सुधार - किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की भूमिका - पैनल चर्चा '(डॉ. राधिका रानी, एनआईआरडीपीआर) पर फोकस किया गया। इसके बाद सतत विकास को हासिल करने के प्रति फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर प्रख्यात व्यक्तियों द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किए गए जैसे कि आईडब्ल्युएमपी (डॉ. के. कृष्ण रेड्डी, एनआईआरडीपीआर, डीडीयू-जीकेवाई, 'आजीविका - राष्ट्रीय आजीविका मिशन' (एनआरएलएम, डॉ. यू. हेमंत कुमार, एनआईआरडीपीआर), 'स्वच्छ भारत' (डॉ. आर. रमेश, एनआईआरडीपीआर), आदि।

प्रतिभागियों ने एनआईआरडीपीआर के ग्रामीण टेक्नोलॉजी पार्क (आरटीपी) का दौरा किया और उन्हें यह जानने का अवसर मिला कि कैसे आरटीपी उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ग्रामीण गरीबों को उचित और सस्ती तकनीकों के व्यापक प्रसार में तेजी से काम कर रहा है। प्रदर्शनी दौरे के भाग के रूप में, प्रतिभागियों को जेएनटीयू हैदराबाद में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बेहतर जल प्रशासन अभ्यास के रूप में विभिन्न जल संचयन संरचनाओं से परिचित कराया गया। डॉ. गिरधर, जेएनटीयू, हैदराबाद)।

अध्ययन दौरे के भाग के रूप में, प्रतिभागियों को कर्नाटक राज्य ले जाया गया। अध्ययन दौरे के दौरान, प्रतिभागियों ने कौशल विकास और जेंडर उद्यमिता को बढ़ावा देने में रुडसेट की पहल के बारे में समझने और जानने के लिए ग्रामीण विकास और स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) - अरसिनकुंटे - बेंगलूरु ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। प्रतिभागियों को मैसूरु जिले के जिला पंचायत के सीईओ से मिलने का अवसर मिला ताकि यह जान सकें कि फोकस करते हुए कैसे विशेष रूप से ग्रामीण भारत पर पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) अपनी सेवाओं को वितरित कर रहे हैं और मैसूर जिला परिषद द्वारा विभिन्न ई-गवर्नेंस पहल को जान सके। टीम ने मैसूरु जिले के हुंसूर तालुक में मनुगनहल्ली ग्राम पंचायत कार्यालय का भी दौरा किया। देवरहल्ली गाँव में, (मनुगनहल्ली जीपी) प्रतिभागियों ने ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ बातचीत की और जानकारी साझा करने और समुदाय के भीतर विकास को देखने के काम में लग गए। टीम ने जीपी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, ई लाइब्रेरी, सड़क निर्माण, पानी और स्वच्छता सुविधाओं और आवास परियोजनाओं जैसे विभिन्न विकास गतिविधियों का अवलोकन किया जो पंचायत संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं। उन्होंने परिषद सदस्यों के साथ-साथ ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से भी मुलाकात की। अध्ययन दौरे के दौरान, संस्थानों के दौरे के अलावा, प्रतिभागियों को कर्नाटक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थानों जैसे कि, श्रवणबेलगोला, बेलूर, हलेबीडु, मैसूरु पैलेस और बेंगलुरु शहर में ले जाया गया।

समापण के दौरान, विदेश मंत्रालय, (एमईए) भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉ. टी वी नागेंद्र प्रसाद, ने इस कोर्स में भाग लेने अपना बहुमूल्य समय देने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को धन्यवाद दिया। उन्होंने इस पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभागियों को नामित करने के लिए सभी 18 देशों के संबंधित विभागों को धन्यवाद दिया। उन्होंने भारत और दुनिया के बाकी हिस्सों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाने के लिए इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के पीछे आईटीईसी -एमईए के महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्यों को समझाते हुए अपने भाषण का समापन किया। महानिदेशक द्वारा की गई टिप्पणी के साथ समापण सत्र समाप्त हुआ।

पाठ्यक्रम के अंत में, सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम से महीने में प्राप्त शिक्षण की रिपोर्ट तैयार की और पाठ्यक्रम टीम को प्रस्तुत किए। सभी प्रतिभागियों ने एक महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यों की समेकित योजना से प्राप्त शिक्षा के आधार पर अपनी स्वयं की कार्य योजना बनाई।

प्रतिभागियों द्वारा मुख्य सीख:

- प्रतिभागियों ने अंतर-सरकारी बैठकों और एकीकृत विकास योजना सत्र जैसे स्थानीय स्तर के प्लेटफार्मों पर सुशासन की पहल को बढ़ावा देना सीखा
- विभाग / संस्था और समग्र रूप से देश के लिए क्या संभव है और क्या संभव नहीं है, इसका मूल्यांकन करना सीखा
- अन्य सरकारी और निजी संस्थानों या अधिकारियों जो भागीदारी के लिए सुशासन और ग्रामीण विकास में शामिल हैं के साथ नेटवर्क और संपर्क स्थापित करना सीखा
- निम्न क्षेत्रों में संभव अनुसंधान विषयों के लिए जमीनी कार्य करना सीखा
- सुशासन
- ई-गवर्नेंस और मोबाइल गवर्नेंस
- सिटीजन रिपोर्ट कार्ड और सामुदायिक स्कोर कार्ड
- सामाजिक लेखापरीक्षा पद्धतियाँ

कार्यक्रम के बारे में प्रतिभागियों के विचार:

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम ने मुझे सिखाया है कि यदि सही तरीके से कई पहलुओं को लागू किया जाता है तो वांछित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मेरे कुछ मुख्य सीख अब मेरे काम के उद्देश्यों का एक हिस्सा हैं वह आगे बढ रहा है और मुख्य रूप से मेरे मंत्रालय के भीतर मेरे मंत्रालय के दायरे में कार्यान्वित परियोजनाओं और परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन में सामुदायिक स्कोर कार्ड और नागरिक रिपोर्ट कार्ड के रूप में सामाजिक जवाबदेही टूल का उपयोग करने का विचार है - **कुडक्काशे गॉडफ्रे कहाबा, जिम्बाब्वे**

2. मुझे उम्मीद है, यदि हमें भारत और अल्जीरिया के बीच सहयोग कार्यक्रम शुरू करना है, तो यह विशेष रूप से डिजिटलाइजेशन के साथ सामाजिक लेखापरीक्षा पर सुशासन के पहलुओं को शामिल करने में होना चाहिए और क्यों न भारत के साथ डिजिटल अल्जीरिया नामक एक सहयोग परियोजना आरंभ किया जाए और ई-शासन, सामाजिक सशक्तिकरण और नागरिक समाज संगठन के क्षेत्र में भारतीय समृद्ध अनुभव साझा करना चाहिए । - **सुश्री लामा हैदर, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया**

3. मैं व्यापक रूप से सिफारिश करता हूं कि एनआईआरडीपीआर कम से कम समय में, पारदर्शी, प्रभावी रूप से अपने सपनों को लागू करने में सरकार की सहायता कर सकता है। अंत में, अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण ने सरकारी सुधारों और शासन के लिए प्रौद्योगिकी के नए युग हेतु परिवर्तन के लिए नए टूल के साथ ग्रामीण विकास के सु-शासन और प्रबंधन पर ज्ञान के साथ प्रतिभागियों को कुशल बनाने के लक्ष्यों को प्राप्त किया है। - **एड्डीव वुगा जैक्सन टोकविन (एमए), प्रोटोकॉल निदेशक, उपाध्यक्ष का कार्यालय, दक्षिण सूडान गणराज्य सरकार**

4. 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए सुशासन' में प्रशिक्षण उपयोगी और प्रासंगिक रहा है। सुशासन और ग्रामीण विकास के संबंध में भारत में शुरू की जा रही पहल और योजनाएं सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखते हुए सभी नागरिकों की समृद्धि सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हैं। - **करेन रूपचंद, सामुदायिक मंत्रालय - गुयाना**

प्रशिक्षण कार्यक्रम के विषयों को व्याख्यान-सह-चर्चा, रोल प्ले, वाद-विवाद, प्रदर्शनी दौरा, समूह अभ्यास, मॉक पंचायतों, समूहों और व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण एवं रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण के विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वितरित की गई।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष और डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर (पाठ्यक्रम निदेशक), सुशासन और नीति विश्लेषण केंद्र (सीजीजीपीए) ने अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर
श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

सहायक संपादक: कृष्णा राज के.एस.
विक्टर पॉल
जी. साई रवि किशोर राजा

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से
डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीडीसी द्वारा प्रकाशित

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन